इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 1 अगस्त 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
सूक्ष्मवित्त ----------5
बीमा----------5
ग्रामीण बैंकिंग ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
विदेशी मुद्रा ----------6
उत्पाद एवं गंठजोड़ ----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7

संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की पहली तिमाही की समीक्षा - 31 जुलाई 2012

नीतिगत उपाय

- पुनर्खरीद (Repo) दर 8% पर अपरिवर्तित।
- प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर 7% पर कायम।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 4.5% पर कायम।
- सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) 11 अगस्त से जमाराशियों के 24% से घटाकर 23% किया गया।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 9.0% पर अपरिवर्तित।

पूर्वानुमान

- वर्ष 2012-13 के सकल घरेलू उत्पाद की निर्देश रेखा वृद्धि का पूर्वानुमान 7.3% से घटाकर 6.5% किया गया।
- मार्च 2013 के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की निर्देश रेखा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया गया।

मुद्रास्फीति सम्बन्धी दृष्टिकोण

- मौद्रिक नीति के संचालन में मुद्रास्फीति के अवबोध को 4.0-4.5% की श्रेणी में रखने और नियंत्रित करने पर बल जारी रहेगा।
- अब तक अपर्याप्त और विषम मानसून का खाद्य सम्बन्धी स्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।
- आगे चल कर खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों पर स्फीतिजन्य दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता।

- खाद्य एवं वस्तुओं की कीमतें, विशेषत: कच्चे तेल की संभावना अनिश्चित हो गई हैं।
- विनिमय दर में उतार-चढ़ावों के कारण निविष्टि की कीमतों का दबाव तथा कोयले, खनिजों एवं बिजली के क्षेत्र में मूलभूत सुविधा सम्बन्धी अड़चनें, खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में वृद्धि कर सकते हैं।

वृद्धि, अर्थव्यवस्था

- अमेरिका और यूरो क्षेत्र से संभाव्य रूप से भारी नकारात्मक अधिप्लावों का जोखिम बढ़ गया है।
- अप्रैल-मई में औद्योगिक गतिविधि के आंकड़ों से यह पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन कुछ पुनरुत्थान के बावजूद कमजोर बना हुआ है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रत्याशा पर बाहरी जोखिम गहन होते जा रहे हैं।
- वर्ष 2012-13 के के लिए एम3 में 15% की वृद्धि तथा वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण में 17% की वृद्धि का पूर्वानुमान कायम रखा गया है।

मुख्य घटनाएं

प्लास्टिक मुद्रा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रयोग

नोटों की जालसाज़ी की घटनाओं के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक प्लास्टिक मुद्रा की शुरूआत करने का प्रयास कर रहा है और वह इसके लिए चार-पांच केन्द्रों में प्रायोगिक परियोजना आरंभ करेगा।

मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों में पांच गुनी बढ़ोतरी

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मोबाइलों के माध्यम से बैंकिंग पांच गुना बढ़ कर (जनवरी-मई 2011 में 209 करोड़ रुपये की तुलना में) जनवरी और मई 2012 के बीच में 1,140.6 करोड़ रुपये हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए मोबाइल बैंकिंग को एक प्रमुख साधन के रूप में अभिज्ञात किया है। पूरे देश में बैंक रहित आबादी की विशाल संख्या

को देखते हुए 229 मिलयन अभिदाताओं वाले मोबाइलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना ईंट और गारे वाले दृष्टिकोण की तुलना में अधिक व्यवहार्य विकल्प माना जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से चेक-आधारित लेनदेन घटाने के लिए कहा

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) से इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को लोकप्रिय बनाते हुए चेक-आधारित लेनदेनों को कम करने के लिए कहा है। बैंकों से चेक-आधारित लेनदेनों में कारबार के परिमाण की दृष्टि से शीर्ष स्तर वाली 20% शाखाओं में कम से कम 20% कमी लाने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय चाहता है कि बैंक ग्राहकों को ई-भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें; क्योंकि किसी चेक के मुद्रण से लेकर भण्डारण और नष्ट करने तक के पूरे जीवन चक्र के दौरान उसके साज-संभाल की लागत बैंक के आकार के आधार पर अत्यधिक अर्थात 25-40 रुपये प्रति चेक होती है।

छोटे मूल्य वाले ई-अंतरणों के लिए बैंक प्रभारों में कमी आएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन प्रभारों को युक्तिसंगत बना दिया है, जो बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) के माध्यम से निधियों के अंतरण के लिए ग्राहकों से वसूल कर सकते हैं। इस मुहिम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की परिधि में लाए जा रहे जन समुदाय को एक कुशल एवं वहनीय विप्रेषण व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना है। 1 अगस्त से बैंक 10,000 रुपये तक की निधियों के अंतरण हेतु (सेवा कर को छोड़ कर) 2.50 रुपये से अनधिक का प्रभार वसूल कर सकते हैं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

व्यापार वित्त संदेशों के लिए साझा मंच

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) से व्यापार वित्त संदेश भेजने के लिए साझी संदेश प्रणाली का उपयोग करने के लिए कहा है। यह साख पत्रों (LCs) को भुनाने और बैंक गारंटियों (BGs) को नकदीकृत करने में होने वाली धोखाधड़ियों को रोकने के लिए है। इसप्रकार 1 अगस्त से कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (SFMS) को छोड़कर कोई भी साख पत्र या बैंक गारंटी जारी अथवा स्वीकार नहीं कर सकता।

उच्चतर पूंजी मानदंड आसन्न

सर्वांगी महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (D-SIB) को अवशोषित करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी की उच्चतर रकम रखनी पड़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के एक पैनल के परामर्शी दस्तावेज़ के अनुसार "हानि के अवशोषण के लिए उच्चतर प्रावधान साझी इक्विटी टियर-1 से पूरे किए जाने चाहिए। किसी बैंक की हानि अवशोषण क्षमता को बढ़ाने और विफलता की संभाव्यता घटाने का यह सबसे आसान और उत्तम तरीका है। देश के सर्वांगी रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान करना और उनके लिए मानदंड निर्धारित करना बैंकिंग विनियामक पर छोड़ दिया गया है। अन्य राष्ट्रीय

विनियामक ऐसी संस्थाओं द्वारा उपस्थित किए जाने वाले जोखिमों से निपटने के लिए अतिरिक्त मानदंड निर्धारित कर सकते हैं।"

अनिवासी जमाराशियों पर कर्मचारियों को कोई ब्याजगत लाभ नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों को स्वयं अपने कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक), अनिवासी विदेशी और अनिवासी साधारण खातों पर 1% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याजगत लाभ देने से रोक दिया है। इसके पूर्व इसके लिए दिए गए विवेकाधिकार को वापस ले लिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए व्युत्पन्नी एक्सपोजर से सम्बन्धित शिथिल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्युत्पन्नी संविदाओं को पुनर्संरचित करने से सम्बन्धित बैंकों के लिए मानदंडों को उन्हें संविदा को परिपक्वता से पहले आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करने की अनुमति देते हुए शिथिल कर दिया है। ऐसे समापन को संविदा की पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते अन्य सभी मापदंड अपरिवर्तित रहें। इसप्रकार बैंकों को समापन के समय उन्हें नकदी के माध्यम से प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य (mark to market) वाले मूल्य पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि व्युत्पन्नी संविदा का दैनिक बाज़ार मूल्य नकदी द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता, तो बैंक (विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं सहित) इस प्रकार की व्युत्पन्नी संविदा परिणत दैनिक बाज़ार मूल्य (MTM) के किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण खातों के अधिग्रहण के मानदंड कठोर बनाए गए

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे किसी अन्य बैंक से ऋण खातों के अधिग्रहण के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीति बनाएं। आम तौर पर, बैंक केवल उन्हीं ऋणों को अधिगृहीत कर सकते हैं, जिनके साख श्रेणी निर्धारण निदेशक मंडल द्वरा अनुमोदित स्तर से अधिक हों। मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि अधिग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों में ऋणों के अनैतिक / अनौचित्यपूर्ण अधिग्रहण को रोकने के लिए उचित कर्तव्यपरायणता (संभाव्य ग्राहक के परिसर / कारखाने के दौरे सहित) बरती जानी चाहिए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों में परिवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को पण्य बाज़ारों में उसके पूर्वानुमोदन के बिना 23% तक निवेश करने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में परिवर्तनों की सूचना दी है। ये परिवर्तन 10 अप्रैल को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा अनुमोदित किए गए थे। देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने की कार्यविधियों को युक्तिसंगत बनाने

के उद्देश्य से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) प्रत्येक वर्ष एक समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परिपत्र जारी करता है। अगला परिपत्र 29 मार्च, 2013 को जारी किया जाएगा।

कृषि उधार लक्ष्यों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड

बैंकरों का कहना है कि खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ऋणों को अब सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSEs) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, बशर्ते ये इकाइयां उनके लिए निर्धारित निवेश मानदंड पूरे करती हों। किसी विनिर्माण इकाई को सूक्ष्म उद्यम रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक न हो और उसके 25 लाख रुपये से अधिक होने पर उसे लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों ही प्रकार के कृषि उधारों के लिए वार्षिक लक्ष्य (समायोजित) निवल बैंक ऋण के 13.5% और 4.5% नियत किए गए हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र उधारों के अन्तर्गत और अधिक सेवाएं

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारों (PSL) के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में 20 या उससे अधिक शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चरणबद्ध रीति से घरेलू बैंकों के समकक्ष लाया जाएगा। उन्हें यह लक्ष्य 1 अप्रैल, 2013 से आरंभ होने वाली अधिकतम 5 वर्षों की अवधि में प्राप्त करना होगा। भारतीय बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य उनके समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% नियत किया गया है। अब महानगरीय शहरों में 25 लाख रुपये तक के तथा अन्य केन्द्रों में 15 लाख रुपये तक के आवास ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। भारत में पाठ्यक्रमों के लिए 10 लाख रुपये तक के और विदेशों में पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत आएंगे। किसानों को छोड़कर व्यक्तियों को गैर-संस्थागत ऋणदाताओं को उनके ऋण चुकाने हेतु 50, 000 रुपये तक के ऋण भी उसके लिए पात्र होंगे।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक से भारत में लिबोर बंटाढार प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कहा गया

अर्थव्यवस्था को एक अन्य वैश्विक वित्तीय संकट से बचाने के प्रयास जारी रहने के बावजूद वित्त मंत्रालय नें भारतीय रिज़र्व बैंक से उन भारतीय बैंकों और कम्पनियों पर लंदन अन्तर-बैंक प्रस्तावित दर (LIBOR) के बंटाढार के निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए कहा है, जिन्होंने विदेशों से धनराशि उधार ले रखी है। लिबोर अपयश को महत्व इसलिए प्राप्त हो गया है, क्योंकि भारतीय

कम्पनियों ने मार्च 2012 तक बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) के माध्यम से 104..4 बिलियन जुटाए हैं, जो देश के 345.82 बिलियन डालर के कुल बाहरी ऋणों के थोड़ा ही कम है। इन विदेशी ऋणों में से अधिकांश लिबोर से सम्बद्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट कार्ड के उपयोग शुल्क की सीमा निर्धारित की

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन ने बताया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारियों को नकदी लेनदेनों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि का चयन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारी बट्टा दरों (उपयोग शुल्क) की एक सीमा निर्धारित की है। 1 सितम्बर से बैंकों के लिए व्यापारी बट्टा दर को 2, 000 रुपये तक के डेबिट कार्ड लेनदेनों पर 0.75% और 2, 000 रुपये से अधिक के लेनदेनों के लिए 1% की दर से सीमित करना जरूरी होगा।

निर्यातकों को विदेशी ऋण सस्ती दरों पर प्राप्त होंगे

विदेशों से उधार लेने के प्रति अनिच्छुक निर्यातकों को एशियाई विकास बैंक तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) जैसी विदेशी ऋण एजेन्सियों द्वारा प्रदान की जा रही ऋण व्यवस्था के माध्यम से कुछ राहत प्राप्त हो सकती है। इन एजेन्सियों द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में प्रदान किए जा रहे ऋण रुपया सावधि ऋणों की तुलना में 4-5% सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि निर्यातकों के पास प्राकृतिक बचाव व्यवस्था मौजूद होती है, क्योंकि उनकी प्राप्य राशियां विदेशी मुद्रा में होती हैं।

विदेशी मुद्रा भेजने अथवा प्राप्त करने पर कोई सेवा कर नहीं

उत्पाद और सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड (CBEC) ने विदेशों से भारत में विप्रेषित विदेशी मुद्रा पर सेवा कर को समाप्त कर दिया है। इससे निर्यातकों, विदेशों में अध्ययनरत छात्रों के परिवारों तथा विदेशों से विप्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा भेजने के लिए लिया गया कोई शुल्क अथवा परिवर्तन प्रभार सेवा कर का भागी नहीं है।

वित्तीय समावेशन के लिए अंकीकरण जरूरी

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDBRT) के निदेशक श्री बी. संबामूर्ति ने कहा है कि वित्तीय समावेशन केवल अंकीकरण (digitisation) के माध्यम से ही लाया जा सकता है। "6.2 लाख गांवों में से केवल 40, 000 बस्तियां ही वित्तीय समावेशन के रडार पर हैं। अंकीकरण की लागत और परिचालनात्मक व्यवहार्यता वित्तीय समावेशन को संभव बनाएगी।"

बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज के भुगतानों पर रोध कर मे कमी सरकार के विचाराधीन

8

पूंजी प्रधान क्षेत्रों, यथा- रेलवे, दूरसंचार और तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के अभियान में वित्त मंत्रालय समस्त बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) और दीर्घावधिक मूलभूत सुविधा बॉण्डों पर ब्याज के भुगतानों पर रोध कर को 20% से घटा कर 5% करने के एक प्रस्ताव पर कार्यरत है। कमतर रोध कर प्रणाली मूलभूत सुविधा कारपोरेट बॉण्डों के लिए रुपये में मूल्यवर्गित ऋण तक भी विस्तारित होगी। इन उपायों से सभी क्षेत्रों को समान अवसर उपलब्ध कराने और रुपया ऋण, जिसमें विदेशी ऋण की तुलना में उच्चतर रोध कर की घटनाएं सामने आती हैं, में सहायता प्राप्त होगी

बैंकरों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से चलनिधि उपायों की मांग

बैंकों के प्रमुखों ने उनके निम्नतम आधार और मार्जिन को संरक्षित करते हुए जमा दरों (और उसके द्वारा उधार दरों) को घटाने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए चलनिधि की सहजता के उपायों की मांग की है। बैंकरों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से इन उपायों की मांग निवेश और कम्पनियों के बीच मनोभावों को बढ़ाने के लिए की है। इस मोड़ पर दुराग्रही मुद्रास्फीति के कारण पुनर्खरीद (repo) दर में कटौती की अपेक्षा आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती अपेक्षाकृत सरल है।

ऋण लेने के लिए लिबोर से बेहतर मिबोर

लंदन अन्तर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) में निर्धारित न्यूनतम दर का उपयोग करने वाले उधारकर्ता यह महसूस करते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (FIMMDA) राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) मिबोर (मुंबई अन्तर-बैंक प्रस्ताव दर) कही जाने वाली यह न्यूनतम दर उस दर को दृढ़ता से प्रतिबिंबित करती है, जिस पर बैंक एक -दूसरे से एक दिवसीय आधार पर उधार लेते हैं। मिबोर के उतार-चढ़ावों की मांग मुद्रा बाज़ार की ब्याज दरों से तुलना करने पर यह पता चलता है कि वे अधिकांशतया यादृच्छिक रूप में घटती-बढ़ती हैं। इसके अलावा, दोनों के बीच अंतर बहुत कम है। सरसरी तौर पर पिछले दो वर्षों की संख्याएं दैनिक-भारित औसत मांग दरों और मिबोर दरों के बीच 0.99 का सह-सम्बन्ध गुणांक दर्शाती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कोई ऋण वृद्धि लक्ष्य नहीं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को उनके कारोबार विकास पर ध्यान नहीं केन्द्रित करना होगा, क्योंकि उनके लिए वर्तमान वित्त वर्ष में ऋण एवं जमा वृद्धि को पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य नहीं होगा। इसके बजाय वित्त मंत्रालय ने उनसे कार्य-कुशलता बढ़ाने और उनकी अनर्जक आस्तियों को घटाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा है। अब बैंकों के समक्ष हानि उठाने वाली शाखाओं की संख्या घटाने तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के (RRBs) के अशोध्य ऋणों को कम करने का लक्ष्य होगा। अब वित्त मंत्रालय चाहता है कि बैंक अपनी लाभप्रदता बढ़ाने तथा आस्ति पर आय, प्रति कर्मचारी निवल

लाभ, आय की तुलना में लागत अनुपात तथा शाखाओं में कर्मचारी अनुपात जैसे मापदंडों पर बल देते हुए आस्ति की गुणवत्ता बढ़ाएं।

पखवाड़े में बैंक ऋण घटे, किन्तु वर्षानुवर्ष 17.7% बढ़े

13 जुलाई को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋणों में 36,400 करोड़ रुपये की कमी आई। हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप उनमें वर्षानुवर्ष 17.7% की बढ़ोतरी हुई। कुल ऋण 47,24,437 करोड़ रुपये रहे।

विदेशी बैंकों ने बड़े शहरों के बाहर विस्तार किया

मध्य भारत को देश में स्थित विदेशी बैंकों के बीच लोकप्रियता हासिल हो रही है। यह आंशिक रूप से विनियामक अनिवार्यता के कारण तो है ही, किन्तु अपेक्षाकृत छोटे कस्बों में बढ़ते कारबार अवसरों के कारण भी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले पांच वर्षों में बड़े विदेशी बैंकों को महानगरीय शहरों में शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दी है। इसके परिणामस्वरूप प्रोद्दातूर, नांद्याल और नांदेड़ जैसे स्थानों को विदेशी बैंकों की शाखाएं हासिल हो गईं। इसलिए, देश में विदेशी ऋणदाताओं के शाखा नेटवर्क में गैर-महानगरीय केन्द्रों के अंश में वृद्धि हो रही है।

कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था के नये मानदंडों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभ में 18% की कमी संभव

स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नये कारपोरेट ऋण पुनर्व्यस्था (CDR) मानदंडों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता पर 18% के स्तर तक का सुदृण नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 12 में सरकार द्वारा नियंत्रित बैंकों की कारपोरेट ऋण पुनर्व्यस्था (CDR) बही 1,17,100 करोड़ रुपये की थी। केवल वित्त वर्ष 12 में ही उनकी पुनर्व्यवस्थित आस्तियों में 62,800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। नये प्रावधानों, जिनके तहत बैंकों को पहले वर्ष में 3% और दूसरे वर्ष में 5% का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा, के कारण यह बढ़ोतरी 3,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

विदेशी बैंकों ने वैश्विक संकट के बावजूद भारत में ऋण जोखिम बढ़ाया

संकटग्रस्त कुछेक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा संभाव्य ऋण चूक के सम्बन्ध में बढ़े संकट के बीच अमेरिका और यूरोप में स्थित विदेशी बैंकों ने मार्च 2012 में समाप्त तिमाही में भारत में अपने ऋण जोखिमों (exposures) में 2.7% की वृद्धि की है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) द्वारा जारी अद्यतन रिपोर्ट से यह पता चलता है कि विदेशी बैंकों के कुल दावे मार्च 2012 के अंत में 283.55 बिलियन अमरीकी डालर के थे, जो दिसम्बर 2011 के 276.12 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक, किन्तु पिछले वर्ष के

सितम्बर के 283.65 बिलियन अमरीकी डालर से थोड़े कम थे। भारतीय निजी कम्पनियों पर विदेशी दावे दिसम्बर के 169.11 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में मार्च 2012 के अंत में बढ़ कर 173.91 बिलियन अमरीकी डालर हो गए, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में वे पिछले वर्ष के अंत में 31.49 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 34.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गए।

विनियामकों के कथन

कृषि ऋण अन्य गतिविधियों में विपथित किए जा रहे हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि अपेक्षाकृत सस्ते कृषि ऋण कृषीतर उद्देश्यों की ओर विपथित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि "कुछेक बैंक शाखाओं के रिकार्डों को देखने पर यह अस्पष्ट था कि किसानों को दिए जा रहे ऋण का उपयोग वास्तविक रूप से कृषि के उद्देश्यों से हो रहा है या नहीं। इससे (किसानों के लिए) सरकारी अनुदान (subvention) योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाता है और इसे या तो सरकारी अनुदान योजना को आशोधित करके या फिर कृषि ऋणों के वास्तविक उपयोग की कठोर निगरानी द्वरा सुधारा जाना आवश्यक है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक का पैनल सोने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने कहा है कि "सोने का आयात भारत के चालू खाते के घाटे में महत्वूर्ण रूप से योगदान कर रहा है। एक पहलू है आयात और दूसरा पहलू है उस सोने को बाहर निकालना जो देश में पहले से मौजूद है। कई एक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यह देखना बाकी है कि क्या इसे मांग को पूरी करने हेतु उपयुक्त वित्तीय लिखत तैयार कर के बाहर निकाला जा सकता है।"

बैंकों द्वारा बहुत सारे किसानों तक पहुंच नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि भारतीय किसानों की काफी बड़ी संख्या अब भी बैंकिंग की परिधि के बाहर है और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वालों को उच्च

ब्याज दर तथा लेनदेन लागत का सामना करना पड़ता है। "काफी हद तक कृषि ऋण में सबसे बड़ी चुनौती मांग-आपूर्ति अंतर है। ब्याज दर सम्बन्धी आर्थिक सहायता देने के बाद भी किसानों के मामले में भारित औसत उधार दर में कमी नहीं आई है। खाद्य सम्बन्धी मुद्रास्फीति से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण संवितरण के लिए कृषि और कृषीतर, दोनों ही प्रकार के कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करना जरूरी है।"

रुपया खुले बाज़ार के परिचालनों से सीधे सम्बद्ध नहीं

11

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि चलनिधि प्रबन्धन परिचालन विनिमय दर में उतार-चढ़ावों से सीधे सम्बन्धित नहीं हैं और रुपये में उतार-चढ़ाव खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) से सीधे सम्बद्ध नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का कहना है कि "रुपये में उतार-चढ़ाव चलनिधि की स्थितियों से सम्बन्धित निर्णयों द्वारा प्रेरित हो रहा है और चलनिधि से सम्बन्धित स्थितियां - चाहे जैसी भी हों, चलनिधि दबाव पैदा कर रही हैं, चाहे वह विदेशी मुद्रा बाज़ार हो या फिर कुछ और हो।"

चालू खाते का घाटा रुपये में गिरावट के लिए गंभीर चिंता

भारत का चालू खाते का घाटा रुपये में अधोमुखी गिरावट के लिए एक गंभीर कारक बना हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का कहना है कि "जैसे ही चालू खाते का घाटा सुधरेगा, चाहे वह तेल की कमतर कीमतों, बढ़े निर्यात अथवा कमतर आयात के कारण हो, इसका उल्टा प्रभाव होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि को सहूलियत के स्तर के भीतर बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है और वह आधार बना रहेगा।"

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ऋण स्वीकृतियों के लिए ऋण ब्यूरो पर आश्रित

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं अब ऋण आवेदनों को अधिकाधिक रूप से ऋण ब्यूरो के माध्यम से प्रेषित कर रही हैं और इनमें से कई एक आवेदन चूकों / अधिक बकाये और बहुविध ऋणों के आधार पर अस्वीकृत किए जा रहे हैं। एस.के.एस. माइक्रोफाइनैंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री एस. दिल्लीराज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऋण आवेदनों की अस्वीकृति की सामान्य दर 8-14% है।

सूक्ष्म ऋणदाताओं की नयी ज़मात व्यवसाय के नियम बदल रही है

विनियामक क्रांति और भारत के सूक्ष्मवित्त क्षेत्र को परिभाषित करने वाली नयी पूंजी के लिए छीना-झपटी के बीच सूक्ष्म ऋणदाताओं की एक नयी ज़मात पारंपरिक मानदंडों को इंटरनेट निधीयन मॉडेल और कम लागत वाले ऋणों के साथ चुनौती दे रही है। महत्वपूर्ण रूप से कमतर ब्याज दरें प्रभारित करते हुए विविध जनसमूहों के उपयोग के माध्यम से संभव बनाए गए अथवा सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों से धन जुटाने के समकक्षी दृष्टिकोण द्वारा इन नवजात उद्यमों ने निवेशकों को प्रतिलाभ प्रदान करते हुए उन समुदायों तक पहुंचने का लक्ष्य नियत कर रखा है, जहां परंपरागत सूक्ष्मवित्त कोई प्रभाव निर्मित करने में विफल रहा है। जहां भारत के सूक्ष्मवित्त क्षेत्र ने लोकोपकारी न्यास निधियों और शामियाने वाले निवेशकों से अनुदानों के माध्यम से नवजात शिशु की भांति डग

भरे, वहीं इंटरनेट और सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग पर आधारित समकक्षी मॉडेल सामाजिक रूप से जागरूक छोटे निवेशक के माध्यम से एक पूर्णत: भिन्न पूंजी समूह निर्मित कर रहा है। छोटे निवेशकों के व्यापक समूह को ऑनलाइन पहुंच से इन सूक्ष्म ऋणदाताओं को सूक्ष्मवित्त के लिए पूंजी के पारंपरिक स्रोत अर्थात बैंकों को दरकिनार करने में सहायता प्राप्त हुई है।

बीमा

सूक्ष्म बीमा क्षेत्र के लिए इर्डा के दिशानिर्देश

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) सूक्ष्म बीमा उद्योग के लिए नये दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) सूक्ष्म बीमा को वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण मानता है और तथा यह चाहता है कि बीमा कम्पनियां सूक्ष्म बीमा क्षेत्र की मांगें पूरी करने हेतु नये उत्पाद विकसित करें। इसके अलावा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) यह भी महसूस करता है कि बेहतर जागरूकता - विशेष रूप से ग्रामीण जन समुदाय में - उन क्षेत्रों में और अधिक गहन पैठ बनाने में उनकी सहायता करेगी।

इर्डा ने व्यापक सूक्ष्म बीमा उत्पाद प्रस्तावित किया

सूक्ष्म बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने और अधिक संस्थाओं को उत्पाद बेचने की अनुमति दे कर उत्पाद पोर्टफोलियो और वितरण नेटवर्क की व्यापकता बढ़ाने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। उसने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और व्यक्तियों (दुकानदारों, औषधि भण्डार के मालिकों, सार्वजनिक टेलीफोन प्रचालकों) को सूक्ष्म बीमा एजेन्टों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। सूक्ष्म बीमा विनियमों में एक ऐसे ढांचे का निर्धारण है, जिसके भीतर बीमाकर्ता इस सम्बन्ध में वहनीय उत्पाद प्रदान कर सकते हैं।

ग्रामीण बैंकिंग

कृषि ऋण से सम्बन्धित अनर्जक आस्तियों में वृद्धि

किसानों के लिए सरकार के ऋण राहत पैकेज की घोषणा के पांच वर्ष के भीतर ही अनर्जक आस्तियों में तीव्र ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति परिलक्षित होने के फलस्वरूप कृषि ऋण खण्ड में एक बार पुन: विपत्ति का जमावड़ा आरंभ हो गया है। कृषि ऋण खण्ड में सकल अनर्जक आस्तियां कृषीतर ऋणों के मामले में 3% के मुकाबले 5% के करीब पहुंच रही हैं। मानसून के कमजोर रहने पर स्थिति और भी खराब हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप फसल की उपज और आय में कमी हो सकती है।

नयी नियुक्तियां

- श्री बी.पी. शर्मा को बैंक ऑफ इंडिया का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री नगेन्द्र मूर्ति तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री रवनीत गिल को ड्यूश बैंक इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विदेशी मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपये में गिरावट का डट कर मुकाबला करने के लिए 7 बिलियन अमरीकी डालर वायदा बाज़ार में बेचा

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा की अपनी प्रारक्षित निधि में किसी प्रकार के अपक्षय के बिना डालर की मांग पूरी करने के लिए वायदा बाज़ार में डालर बेच रहा है। वायदा बाज़ार में हस्तक्षेप करने से होने वाला एक लाभ यह है कि आवश्यक होने पर डालर की आपूर्ति की, वह भी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का आवक्षय किए बिना प्रतिबद्धता होती है। इस प्रकार की संविदाओं को निरस्त भी किया जा सकता है। ऐसी रणनीति वायदा रक्षा पर प्रीमियम को रोकने में सहायक होती है, क्योंकि आयातकों ने भी रुपये की उच्च अस्थिरता को प्रतिरक्षित करने के लिए (वायदा) रक्षा के लिए आपा-धापी शुरू कर दी थी।

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 589 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि 20 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 589 मिलियन अमरीकी डालर बढ़ कर 287.33 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं। प्रारक्षित निधियां बैंकों की विदेशी मुद्रा आस्तियों में 565.5 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि के

कारण बढ़ीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रारक्षित निधियों की स्थिति 2.131 बिलियन अमरीकी डालर थी।

अगस्त 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष

अमरीकी डालर	1.05350	0.422	0.480	0.625	0.787
जीबीपी	1.48838	0.7950	0.8211	0.9150	1.0570
यूरो	0.90393	0.603	0.698	0.855	1.050
जापानी येन	0.55229	0.301	0.300	0.325	0.368
कनाडाई डालर	2.050 50	1.363	1.446	1.540	1.635
आस्ट्रेलियाई डालर	4.54600	3.220	3.280	3.470	3.550
स्विस फ्रैंक	0.37140	0.083	0.100	0.190	0.298
डैनिश क्रोन	0.82500	0.5250	0.6290	0.8020	1.0110
न्यूजीलैंड डालर	3.47000	2.780	2.950	3.095	3.235
स्वीडिश क्रोनर	2.71000	1.830	1.838	1.889	1.963

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**20 जुलाई 2012 के दिन**	**20 जुलाई 2012 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	15, 876, 6	2, 87,338 7
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 068.9	2, 55,102. 2
ख) सोना	1, 450, 6	25, 760. 2
ग) विशेष आहरण अधिकार	239, 6	4, 345.0
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	117.5	2, 131.3

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य

14

इंडसइंड बैंक	सुजुकी मोटर साइकिल	बैंक सुजुकी के दुपहिया वाहन ग्राहकों को उसके 250 व्यापारी प्रतिष्ठानों में खुदरा वित्त प्रदान करेगा।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

संकट के दौरान दबाव परीक्षण के कार्य-निष्पादन की जांच

वित्तीय संकट ने चार व्यापक क्षेत्रों में खलबली की शुरूआत के पहले अपनाई जाने वाली दबाव परीक्षण प्रथाओं को रेखांकित किया है : (i) दबाव परीक्षण और जोखिम अभिशासन में एकीकरण का उपयोग; (ii) दबाव परीक्षण की कार्यप्रणालियां; (iii) परिदृश्य चयन; और (iv) विशिष्ट जोखिमों और उत्पादों का दबाव परीक्षण।

दबाव परीक्षण और जोखिम अभिशासन में एकीकरण का उपयोग

बैंकों के जोखिम अभिशासन और पूंजी आयोजना में दबाव परीक्षण के यथोचित उपयोग को सुनिश्चित करने में बोर्ड और वरिष्ठ प्रबन्धन की संलग्नता महत्वपूर्ण होती है। इसमें दबाव परीक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना, परिदृश्यों को निर्धारित करना, दबाव परीक्षण के परिणामों पर चर्चा करना, संभाव्य कार्रवाइयों का निर्धारण करना और निर्णय लेना शामिल हैं। उन बैंकों में जो वित्तीय संकटों के प्रति अत्यधिक असुरक्षित थे तथा तुलनात्मक रूप से अच्छा कार्य किया था, कुल मिला कर वरिष्ठ प्रबन्धन ने दबाव परीक्षण के विकास और परिचालन में सक्रिय रुचि ली थी, जिसमें रणनीतिक निर्णय लेने में दबाव परीक्षण के परिणामों ने निविष्टि (सूचना) का काम किया था। हालांकि, अधिकांश बैंकों में दबाव परीक्षण के कार्यों से आंतरिक बहस की शुरूआत नहीं हो पाई, न ही लागत, जोखिम और गति जैसी उन पूर्व मान्यताओं को चुनौती मिल सकी, जिससे नयी पूंजी जुटाई जा सके अथवा विदेशी मुद्रा के क्रय और विक्रय की स्थितियों को प्रतिरक्षित किया जा सके अथवा उन्हें बेचा जा सके।

वित्तीय संकट ने दबाव परीक्षण कार्यक्रमों के संगठनात्मक पहलुओं में मौजूद कमजोरियों को भी उजागर किया है। संकट के पूर्व कुछेक बैंकों में दबाव परीक्षण मुख्यत: व्यवसाय क्षेत्रों के साथ मामूली संवाद के साथ जोखिम कार्यों द्वारा एक पृथक कार्य के रूप में किया जाता था। इसका अर्थ यह हुआ

कि अन्य बातों के साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र प्राय: यह मानते थे कि विश्लेषण विश्वसनीय नहीं था। इसके अलावा, कुछेक बैंकों में दबाव परीक्षण कार्यक्रम एक यांत्रिक अभ्यास था। जहां किसी व्यापक दबाव परीक्षण कार्यक्रम (यथा पृष्ठभूमि की निगरानी) के भीतर नेमी तौर पर किए जाने वाले दबाव परीक्षण की गुंजाइश होती है, वहीं वे संपूर्ण स्थिति को सामने नहीं लाते, क्योंकि यांत्रिक दृष्टिकोण न तो कारबार की बदलती स्थितियों को ध्यान में रख सकते हैं और न ही किसी बैंक के विभिन्न क्षेत्रों से गुणात्मक निर्णयों को शामिल कर सकते हैं। इसके भी अलावा, कई एक बैंकों में दबाव परीक्षण अलग इकाइयों द्वारा कारबार के विशिष्ट क्षेत्रों अथवा जोखिम के प्रकारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए किए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप किसी बैंक में मात्रात्मक और गुणात्मक दबाव परीक्षण परिणामों को एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित करते समय संगठनात्मक रुकावटें पैदा हो जाती थीं।

संकट के पूर्व कई एक बैंकों ने मेहराबदार दबाव परीक्षण कार्यक्रम नहीं लागू किए थे, अपितु विशिष्ट जोखिमों अथवा पोर्टफोलियो के लिए फर्म स्तर के सीमित एकीकरण के साथ अलग से दबाव परीक्षण किया करते थे। जोखिम विशिष्ट दबाव परीक्षण सामान्यतया व्यवसाय क्षेत्रों के भीतर ही किया जाता था। जहां बाज़ार और ब्याज दर जोखिम के लिए दबाव परीक्षण कई वर्षों से किए जाते रहे हैं, वहीं बैंकिंग बही में ऋण जोखिम के लिए दबाव परीक्षण अभी हाल ही में विकसित हुआ है। अन्य दबाव परीक्षण अभी तक अपने शैशवकाल में ही हैं। फलत: सह-सम्बद्ध अंतिम सिरे वाले एक्सपोजरों और पूरे बैंक में जोखिम संकेन्द्रणों पहचानने की अपर्याप्त योग्यता मौजूद थी।

दबाव परीक्षण के ढांचे सामान्यत: इतने लचीले नहीं थे कि संकट पैदा होने पर उन पर शीघ्रतापूर्वक अनुक्रिया (अर्थात एक्सपोजरों का शीघ्रतापूर्वक संयोजन करने, नये परिदृश्यों को लागू करने अथवा मॉडेलों को आशोधित करने की असमर्थता) हो। सूचना प्रौद्योगिकी की मूलभूत संरचना में और अधिक निवेश आवश्यक हो सकते हैं। जोखिम से सम्बन्धित उस सूचना की उपलब्धता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए जो तीव्र गति से बदलते परिवेश से निपटने के लिए तैयार किए गए नये दबाव परिदृश्यों के प्रभाव का समय पर विश्लेषण एवं आकलन करने में समर्थ बनाएगी। उदाहरण के लिए चलनिधि प्रबन्धन सूचना प्रणालियों में निवेश करना जो दिवसांत की सूचना को स्वचालित करने की किसी बैंक की योगयता बढ़ाएगी, भार-रहित आस्तियों के सम्बन्ध में अधिक उपयोगी सिद्ध होगी तता कारोबारी इकाइयों के तुलनपत्र की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाएगी।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

वाई- शेयर

पारस्परिक निधि शेयरों की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्राय: प्रति समूह 500,000 अमरीकी डालर जैसे उच्च न्यूनतम निवेश और उत्सर्जित अथवा सीमित भार प्रभारों एव शुल्कों की अपेक्षा होती है। उच्च न्यूनतम निवेश अपेक्षित होने के कारण, वाई शेयर प्राय: केवल बड़े संस्थागत निवेशकों को ही प्राप्य होते हैं।

शब्दावली

संरचनागत वित्तीय संदेश प्रणाली

संरचनागत वित्तीय संदेश प्रणाली (SFMS) अंत: बैंक और अंतर-बैंक अनुप्रयोगों के लिए एक प्लेटफार्म का कम करने हेतु विकसित सुरक्षित संदेश मानक है। यह विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति (स्विफ्ट), जो वैश्विक स्तर पर वित्तीय संदेशों के लिए प्रयुक्त होने वाली अंतरराष्ट्रीय संदेश प्रणाली है, जैसा ही भारतीय मानक है। संरचनागत वित्तीय संदेश प्रणाली की शुरूआत 14 दिसम्बर, 2001 को बैंकिंग प्रणाली में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDBRT) में की

गई थी। संरचनागत वित्तीय संदेश प्रणाली में कई एक खास विशेष विशेषताएं हैं और यह लचीली संरचना वाले केन्द्रीकृत अथवा वितरित परिनियोजन को सुगम बनाने वाला एक मॉड्यूलरीकृत और वेब -समर्थित सॉफ्टवेयर है।

संस्थान की गतिविधियां

आईआईबीएफ, लीडरशिप सेंटर में अगस्त - सितम्बर, 2012 की तिमाही के लिए नियोजित प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	अनुपालन कार्य- कार्यशाला	24 अगस्त
2	व्यापार वित्त	3 से 7 सितम्बर
3	संपदा प्रबन्धन	10 से 12 सितम्बर

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ - विज़न का ई-मेल द्वारा प्रेषण

संस्थान अक्तूबर 2012 के बाद से आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, यदि वे पहले न पंजीकृत कराए गए हों, तो तत्काल पंजीकृत करा लें। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

साधारण सदस्यता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

संस्थान ने 15 जून, 2012 से साधारण सदस्यता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कर दिया है। इसके बाद से संस्थान पंजीकरण हेतु सदस्यता फार्म और मांग ड्राफ्ट नहीं स्वीकार करेगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

सदस्यता शुल्क में सेवा कर का समावेश

18

सेवा कर के कारण साधारण आजीवन सदस्यता शुल्क में 185 रुपये की वृद्ध हो गई है। संशोधित साधारण सदस्यता शुल्क 1,685 रुपये है।

मुख्य (मास्टर) परिपत्र

संस्थान ने महत्वपूर्ण मुख्य (मास्टर) परिपत्र अपने पोर्टल पर डाल रखे हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी परीक्षां की तैयारी करते समय सम्बन्धित मुख्य (मास्टर) परिपत्र देख लें।

कागज़ रहित (नयी) पहलकदमी

कृपया संस्थान के ास मौजूद अपने ई-मेल पते को अद्यन करवा लें, ताकि वह भाविष्य में वार्षिक रिपोर्टें ई-मेल द्वारा भेज सके।

सूक्ष्म / स्थूल शोध

संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए सूक्ष्म / स्थूल शोध के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www. iibf.org.in देखें।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

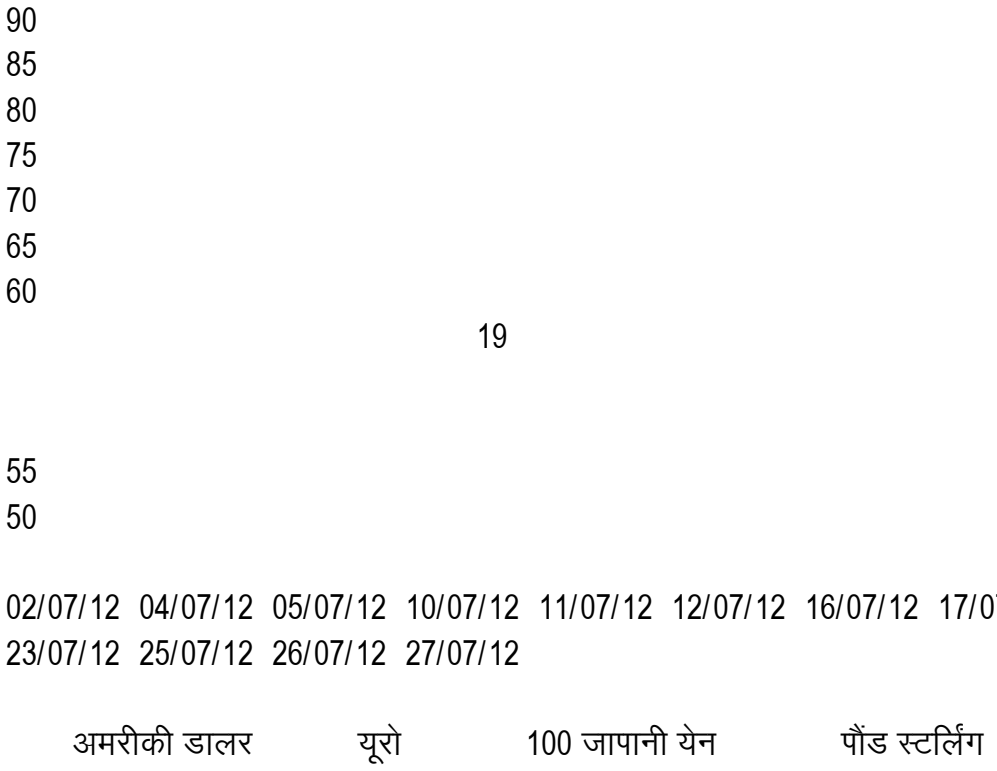

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- मार्च से लुढ़कते रहने के बाद रुपये ने अंत में दिशा बदली। पिछले दो सप्ताहों में अमरीकी डालर के समक्ष भारतीय रुपये में मज़बूती आई जिससे वह 54.37 पर बंद हुआ तथा यूरो के समक्ष 68.46 की दर पर मज़बूत दिखा।
- 10वीं को रुपया लुढ़क गया, चार दिनों की अपनी गिरावट के सिलसिले के बाद 53 पैसे की बढ़त ले कर वह 55.39 पर बंद हुआ, क्योंकि यूरोपीय संघ के ऋणदाताओं के स्पेनी बैंकों की जमानत (bailout) पर सहमत हो जाने के परिणामस्वरूप अमरीकी मुद्रा की कमजोरी को देखते हुए डालर की आपूर्ति मांग से अधिक रही।
- कमतर व्यापार घाटे के कारण निर्मित सकारात्मक मनोभाव के फलस्वरूप निर्यातक डालर बेचने लगे, जिससे रुपया मज़बूत हो कर 13वीं को 55.15 पर बंद हुआ।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा डालर की भारी खरीद और कमजोर यूरो के परिणामस्वरूप 20वी को रुपया अमरीकी डालर के मुकाबले 55.33 के अंत: दिवसीय कम स्तर पर बंद हुआ।
- वैश्विक जोखिम विरुचि के कारण माह के दौरान रुपया सर्वाधिक न्यून स्तर पर पहुंच गया और 23वीं को 55.98 पर बंद हुआ।
- इस अटकल पर कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंक उच्चतर प्रतिफल वाली आस्तियों की मांग को बढ़ावा देते हुए वृद्धि को सहारा देने के लिए और उपाय करेंगे, लगभग दो सप्ताहों में रुपये में सर्वाधिक मज़बूती आई। रुपया डालर के समक्ष 1.2% बढ़ कर 55.52 पर पहुंच गया, जो 13 जुलाई के बाद से सबसे बड़ा उछाल है।

भारित औसत मांग दरें

8.30
8.20
8.10
8.00
7.90
7.80
7.70
7.60

20

7.50

03/07/12 05/07/12 09/07/12 11/07/12 14/07/12 16/07/12 19/07/12 20/07/12 21/07/12 23/07/12 27/07/12

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- उधार लेने वाले बैंकों से अच्छी मांग पर एक दिवसीय मांग मुद्रा बाज़ार में मांग मुद्रा की दर में वृद्धि हुई और वह 5वीं को 8% पर बंद हुई।
- मांग दरें 8.20% और 8% के बीच मंडराती रहीं तथा प्रणाली में प्रचुर चलनिधि की मौजूदगी के बीच उधार लेने वाले बैंकों से मांग के अभाव के कारण 14वीं को घट कर 7.85% पर आ गईं।
- अंतर-बैंक मांग दरें 20वीं जुलाई को 8.04% के बंद वाले स्तर से घट कर 21वीं को 7.66% हो गईं।
- मांग दरें श्रेणीबद्ध बनी रहीं और 7.66%se 8.20% के बीच घटती-बढ़ती रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

17700
17500
17300
17100
16900
16700
15500

02/07/12 05/07/12 09/07/12 10/07/12 11/07/12 17/07/12 19/07/12 23/07/12 24/07/12

25/06/12 26/07/12 27/07/12

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अगस्त, 2012